नगर निगम में पौधारोपण के नाम पर लूट कमाई की तैयारी जारी किए गए दो करोड़ रुपये के टेंडर

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) विकास के नाम पर दौ सौ करोड़ रुपये डकारने वाले नगर निगम के अधिकारी अब पौधारोपण के नाम पर लूट कमाई करने की तैयारी कर रहे हैं। बीते वर्ष के पौधारोपण का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है और इस वर्ष हरियाली के नाम पर फिर करोड़ों रुपये की बंदरबांट की जाएगी।

शहर की ग्रीन बेल्ट विकसित करने, हरियाली बढ़ाने और काष्ठ वाले पेड़ विकसित करने के लिए नगर निगम ने इस वर्ष भी 2,66,31,285 रुपये के टेंडर जारी किए हैं। यह धन सभी वार्डों के लिए नहीं बल्कि नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज चल रहे तिगांव विधायक राजेश नागर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कुछ वार्डों पर खर्च किया जाएगा। बताते चलें कि नरेंद्र गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण के नाम पर 49 लाख रुपये डकारने का आरोप यादव कोऑपरेटिव नाम की ठेकेदार कंपनी पर लगा कर हंगामा किया था। ठेकेदार ने न तो पौधे लगाए और न ही फेंसिंग करवाई और निगम अधिकारियों ने उसे भुगतान कर दिया था। विधायक की नाराजगी पर अधिकारी लीपापोती में जुट गए थे। अब बीते वर्ष का हरियाली का लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं निगम अधिकारियों ने फिर से टेंडर निकाल दिए।

निगम के भ्रष्ट और चालाक अधिकारियों ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 28-34 में ग्रीन बेल्ट और रोड साइड पर (टिंबर ट्री के) पौधे लगाने के दो टेंडर जारी किए हैं, एक 95,29,240 का और दूसरा 47,63,195 रुपयों का। 28-34 वार्ड में की जाने वाली इस हरियाली के लिए दो टेंडर इसलिए जारी किए गए क्यों कि एक्सईएन को एक करोड़ रुपये तक के ही टेंडर स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। ऐसे में जानबूझ कर एक ही काम के लिए दो टेंडर जारी किए गए। बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश गोयल इसे भ्रष्टाचार की तैयारी बताते हैं, उनके मुताबिक एक ही काम एक ही टेंडर का कि या जाएगा लेकिन दो जगह दिखा कर लाखों की हिस्सा बांट हो जाएगी। सरकार का यह भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है आए दिन करोड़ों के घोटाले और हेराफेरी सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके एक्सईएन को एक करोड़ रुपये तक के टेंडर जारी करने की शक्ति देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही है।

इसके अलावा विधायक राजेश नागर की विधान सभा में वार्ड नंबर 22 से 27 के बीच 22,67,250 रुपये से पौधरोपण, ट्री गार्ड और ग्रीन बेल्ट को हराभरा करना है। राजेश नागर भी निगम अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हुए तो उनके इलाके के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया।

सच्चाई ये है कि पौधारोपण की मोटी कमाई काम जन प्रतिनिधि अपने खास ठेकेदारों को ही दिलवाते हैं, यही कारण है कि काम नहीं होने पर भी कोई कुछ नहीं कहता। यदि कोई ठेकेदार नेताजी को खुश नहीं करता तो फिर नेताजी उसके कार्यों की जांच कर हल्ला गुल्ला करते हैं और निगम अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं जैसे ठेकेदार ने सभी पौधे और ट्री गार्ड लगा दिए हों।

सुरेश गोयल कहते हैं कि पौधरोपण के नाम पर हमेशा खेल होता है। ठेकेदार मई-जून में पौधे लगाया जाना दिखाता है। जिस समय नगर निगम अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध करा पाता उस समय पौधों को पानी कौन देगा? फिर बताया जाता है कि पौधे सूख गए। अब क्योंकि पौधे ही नहीं बचे तो दिखाने के लिए इक्का दुक्का ट्री गार्ड लगाकर बाकी धन ठेकेदार और अधिकारियों की जेब में चला जाता है।

बीते दस साल में जितना धन पौधारोपण के नाम पर खर्च किया गया है उसके आधार पर तो पूरा शहर अभी तक हराभरा हो जाना चाहिए था। इसके विपरीत वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2017-2019 के बीच फरीदाबाद में 0.06 प्रतिशत हरियाली घटी है। यही नहीं अरावली संरक्षित वन क्षेत्र में वनाच्छादन का घनत्व भी अलग-अलग इलाकों में 10 से 25 फीसदी तक कम हुआ है। ऐसा तब है कि शहर में केवल नगर निगम ही पौधरोपण नहीं करवा रहा, हूडा, वन विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी सरकारी महकमे भी पौधरोपण का लक्ष्य पूरा करते हैं। इनके अलावा एनजीओ, आरडब्ल्यूए, पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं भी प्रत्येक वर्ष हजारों पौधे लगाती हैं, इन संस्थाओं के लगाए पौधे तो जीवित भी रहते हैं लेकिन सरकारी महकमों और खासकर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर लगाए पौधे, ग्रीन बेल्ट अपने ट्री गार्ड सहित समाप्त हो जाते हैं। विधायक, सांसद और मंत्री भी प्रत्येक वर्ष पौधरोपण कर फोटो अखबारों में छपवाते हैं लेकिन पौधे जिंदा हैं या मुरझा गए यह सवाल किसी अधिकारी से नहीं पूछते।

फर्जी कंपनी को दिया ठेका तभी तो नहीं बनी सड़क

दस लाख तक के काम करने वाली जे एस सिनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया सात करोड़ का काम, तो रुकना ही था

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) गुड़गांव में फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम पाने वाली जे एस सिनर्जीज़ कंपनी का टेंडर कैंसिल किए जाने की बात जानते हुए भी एफएमडीए अधिकारियों ने इस कंपनी को सेक्टर 15-15ए का निर्माण कार्य सौंप दिया। फर्जी कंपनी और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम यह है कि काम शुरू होने के पांच महीने बाद भी यह वीआईपी सड़क अधूरी पड़ी है और आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

गुड़गांव की जे एस सिनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने मई-जून 2022 में गुड़गांव कैनाल पर वड़ोदरा एक्सप्रेस से नेशनल हाइवे 19 दिल्ली-आगरा के बीच का टेंडर हासिल किया था। केवल दस लाख रुपये तक का निर्माण कार्य कराने वाली कंपनी के प्रबंधन ने टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी वर्क एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट लगाए थे। शिकायत होने पर इसकी जांच के लिए टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी (टीईसी) गठित की गई थी। सिंचाई विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में गठित टीईसी ने जांच रिपोर्ट में कंपनी का वर्क एक्सपीरिएंस फर्जी होना बताया था। इसके आधार पर कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। कंपनी की जांच करने के भी आदेश जारी किए गए थे। फर्जी दस्तावेज के कारण जे एस सिनर्जीज़ का टेंडर रद्द किए जाने की खबरें भी छपीं थीं।

इसके बावजूद एफएमडीए के अधिकारियों ने सितंबर 2022 में सेक्टर 15-15ए में आरएमसी सड़क, फुटपाथ और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आदि निर्माण के लिए 8.25 करोड़ रुपये की टेंडर प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम और एफएमडीए में सक्रिय टेंडर हड़पने के सिंडिकेट ने यहां भी बोली लगाई। अब क्योंकि टेंडर जे एस सिनर्जीज़ को ही दिया जाना था इसलिए आरके जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट ने अनुमानित लागत से 24.69 प्रतिशत, आरके गांधी ने 9.93 प्रतिशत और कमल बिल्डर्स ने 10.72 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई। जे एस सिनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमानित लागत से 7.09 प्रतिशत कम यानी 7,67,2,003 रुपये की बोली लगाई। कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। कंपनी को छह माह में काम पूरा करना था। इस बीच ठेकेदारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने एफएमडीए अधिकारियों से जे एस सिनर्जीज़ के दागी होने की शिकायत की लेकिन अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल, वीआईपी सड़क के निर्माण का ठेका इस कंपनी को दिलाने के लिए कुछ 'वीआईपी' का दबाव था इसलिए विरोध के बावजूद अधिकारी कंपनी का पक्ष लेते रहे।

अब कंपनी को इतने बड़े काम का एक्सपीरिएंस तो था नहीं इसलिए आधी अधूरी सड़क तो बना दी लेकिन फुटपाथ और सबसे अहम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम छूट गया। बारिश में जलभराव हुआ तो आला अधिकारियों ने नाराजगी जताई, ऐसे में एफएमडीए के चुक चुके अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए कंपनी प्रबंधन पर टूट पड़े। अनुमानित लागत से नीचे टेंडर डालने, सुविधा शुल्क चुकाने के बाद कंपनी को भी यह प्रोजेक्ट फायदे का सौदा नहीं नजर आ रहा, इसलिए फिलहाल काम रुका हुआ है और पूरा होने के आसार भी नगण्य हैं। अब देखना है कि एफएमडीए के अधिकारी काम पूरा न करने के लिए दागी कंपनी को दंड देंगे या इसकी लागत बढ़ाने का जुगाड़ कर कंपनी को हो रहे नुकसान की भरपाई और मुनाफा कराया जाएगा।

अधिकारियों को ठेंगे पर रखने वाली मुनेश चौधरी आई पहाड़ के नीचे

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पद खरीद कर डीईओ बनने के बाद लाखों की हेराफेरी करने और अधिकारियों को ठेंगे पर रखने वाली मुनेश चौधरी सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्म का फल भोगेगी। सेटिंग-गेटिंग में माहिर पति धर्म सिंह ने मुख्यालय से लेकर सचिवालय और सत्तापक्ष के नेताओं तक से पैरवी करवा मुनेश को जांच से तो बचा लिया लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपनी टांग अड़ा दी है। घपलों और लापरवाहियों के बावजूद जो आला अधिकारी शिक्षामंत्री के कहने पर मुनेश के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्पष्टीकरण तलब कर उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे अब कोर्ट ने उन्हें भी जवाब देने के लिए तलब किया है। अगर जांच सिरे चढ़ी तो मुनेश चौधरी की पेंशन तो बंद होगी ही रिकवरी भी हो सकती है।

वर्तमान में छुट्टी पर चल रही डीईओ मुनेश चौधरी पर 2005 में उनके डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर रहते हुए 25.79 लाख रुपये गबन करने और इनमें से पांच लाख रुपये निजी खाते में डालने का आरोप उप निदेशक एससीईआरटी ऋतु चौधरी ने लगाया था। इस मामले में शहर के ऋषि कुमार ने न्यायालय के जरिए सेक्टर 17 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन सत्ताधारियों के करीबी मुनेश के पति धर्म सिंह ने पत्नी पर जांच की आंच नहीं आने दी और पुलिस को तफ्तीश ठंडे बस्ते में सरकानी पड़ गई। इधर मुनेश चौधरी के कार्यालय से वही खास दस्तावेज संदिग्ध रूप से गायब हो गए जिनमें 25.79 लाख रुपये का हिसाब किताब था। यह रिकॉर्ड लेखाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय से भी संदिग्ध रूप में गायब हो गया। बस इसे आधार बना कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं समझी। डीसी, एडीसी की लगातार विपरीत टिप्पणियों और आला अधिकारियों को भेजी गई शिकायती रिपोर्टें का भी मुनेश चौधरी पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे कार्यकाल में उन्होंने न शिक्षा विभाग और न ही प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया, बल्कि मातहत को भेज कर काम चलाया। अधिकारी ने दबाव बनाया तो छुट्टी पर चले जाना उनकी कार्य शैली रही है।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी आदि फंड मिलने में गबन की राशि अड़चन न बने इसलिए इसी महीने सेवानिवृत्त हो रही मुनेश चौधरी ने मुख्यालय को पत्र लिखकर उन पर लगे यह आरोप समाप्त किए जाने की प्रार्थना की है। पति धर्म सिंह इन आरोपों को समाप्त कराने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों से लेकर शिक्षामंत्री के कार्यालय तक की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन उनके इस प्रयासों पर ऋषि कुमार ने तुषारापात कर दिया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाल कर इस मामले में अधिकारियों की हीलाहवाली पर निशाना साधा है। अब हाईकोर्ट ने राज्य के प्रधान सचिव और वित्तायुक्त के जरिए सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही डीसी फरीदाबाद, पुलिस आयुक्त फरीदाबाद, एसएचओ सेक्टर 17 थाना को भी तलब किया है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।